क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 16, शुक्रवार, 08 फरवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

यूपी-बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, इन शहरों में भी चलेगी मेट्रो

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। पटना, कानपुर, आगरा के लिए मेट्रो और मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल सिस्टम के लिए पब्लिक इन्वेंस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) में सहमति बन गई है। इसमें अहमदाबाद मेट्रो का फेज दो भी शामिल है। अब इन प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा। सरकार की कोशिश लोकसभा चुनावों के पहले इन परियोजनाओं को शुरू कर इन शहरों से जुड़े लोगों को तोहफा देने की है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले पब्लिक इन्वेंस्टमेंट बोर्ड की दो दौर में हुई बैठकों में इन पर सहमति बनी है। बैठक में वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव (व्यय), शहरी विकास मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, रेलवे बोर्ड, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के साथ संबंधित राज्यों के अधिकारी मौजूद थे। एजेंडा बड़ा होने के कारण दो बैठकें हुई। एक बैठक में आगरा और कानपुर की मेट्रो के साथ दिल्ली मेरठ आरआरटीएस को लिया गया, जबकि दूसरी बैठक में पटना व अहमदाबाद मेट्रो के मामले रहे। सूत्रों के अनुसार अब इन मामलों को जल्द ही कैबिनेट के सामने लाया जाएगा, ताकि मंजूरी के साथ जल्द शुरुआत की जा सके। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। ऐसे में सरकार की कोशिश इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास इसी महीने करने की है, ताकि चुनाव से पहले इनकी शुरुआत हो सके। प्रस्ताव के मुताबिक पटना मेट्रो को पांच साल में पूरा कर लिया जाएगा। शहर में दो मेट्रो कोरीडोर बनाए जाने हैं। पहले कोरीडोर को दो-तीन साल में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। दोनों चरणों में 31.39 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाई जानी है। कानपुर व आगरा के भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों को मेट्रो से भारी राहत मिलेगी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल से दोनों शहरों की बीच की दूरी महज 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी।

भाजपा के हित में संघ और विहिप ने राम मंदिर मुद्दा पीछे धकेल दिया

संघ और विहिप, दोनों ने अदालत के फैसले का इंतजार करने का इरादा छोड़ दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वह अध्यादेश जारी करें

नई दिल्ली।

कुंभ के अवसर पर आयोजित धर्म-संसद में विश्व हिंदू परिषद ने जो घोषणा की है, उसके कारण देश के रामभक्त बेहद परेशान दिख रहे हैं। उन्हें आशा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विहिप के दबाव के चलते मोदी सरकार राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में तुरंत शुरू कर देगी। संघ और विहिप, दोनों ने अदालत के फैसले का इंतजार करने का इरादा छोड़ दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वह अध्यादेश जारी करें। लेकिन अब इन संगठनों ने अगले चार-पांच माह के लिए चुप्पी साध ली है। वे न तो कोई मांग करेंगे और न ही कोई आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसे वे एक घटिया चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते। इसमें शक नहीं कि इस मुद्दे को लेकर सारे दल जूतों में दाल बांटते और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे खूंटी पर टंग जाते। सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा का होता। उसकी दशा कांग्रेस-जैसी हो जाती। जो नई सरकार बनती, उसका क्या पता, वह कैसी होती ? शायद वह राम मंदिर के मुद्दे को मोदी सरकार की ही तरह दरी के नीचे सरका देती। या खुद राम मंदिर खड़ा करके वह भाजपा, संघ और विहिप की जड़ों को मट्ठा पिला देती। कांग्रेस ने तो ऐसा संकेत भी दे दिया है। इस मामले में मेरी स्पष्ट राय है कि यह मामला न अदालत सुलझा सकती है और न ही कोई आंदोलन ! ये दोनों रास्ते ऐसे हैं, जिनसे राम-मंदिर का मामला आगे जाकर भारत के गले का पत्थर बन जाएगा। इस मामले का स्थायी और सर्वमान्य हल यह है कि अयोध्या की इस कुल 70 एकड़ जमीन में एक सर्वधर्म तीर्थ खड़ा किया जाए, जहां राम का अपूर्व विश्व-स्तरीय सुंदर मंदिर बने और शेष स्थानों पर भारत के ही नहीं, विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के पूजास्थल बन जाएं। उनका एक संग्रहालय और पुस्तकालय भी बने। सरकार ने अधिग्रहीत जमीन उसके मालिकों को वापिस लौटाने की जो याचिका अदालत को दी है, वह उसने उचित नहीं किया है। उसे वह तुरंत वापस ले। स्वामी स्वरूपानंदजी भी तीनों याचिकाकर्ताओं से बात करें। उन्हें सहमत करवाएं। 21 फरवरी से आंदोलन न छेड़ें। सांसारिक नौकरशाहों के नौकरों याने हमारे नेताओं पर आध्यात्मिक कृपा करें। उनकी बुद्धि और विवेक को जागृत करें।

लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल

अहमदाबाद। गुजरात के पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल ने बुधवार को ऐलान किया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हार्दिक ने हालांकि यह नहीं बताया कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लडेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वह चुनाव लड़ने के लिये पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के झुझनु ज़िले में जज़्बा जीत का लक्ष्य 2019 न्यू राजस्थान शिक्षा ग्रुप के हज़ारों छात्र को संबोधित किया.यह छात्र मेरे हिंदुस्तान का भविष्य हैं।मंजिल उन्हीं को मिलती है,जिनके सपनों में जान है।पंख से कुछ नहीं होता,हौसलो से ही उड़ान है। इंक़लाब ज़िंदाबाद लखनऊ में पत्रकारों द्वारा चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर हार्दिक ने कहा, ÷बिल्कुल, हम 2019 में चुनाव लड़ेंगे।÷ कांग्रेस में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता ने कहा कि वह इस बारे में बाद में फैसला करेंगे।

ममता बनर्जी, गृह मंत्रालय से पुलिस प्रमुख पर नहीं मिला कोई नोटिस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का अभी कोई नोटिस नहीं मिला है। बनर्जी ने सचिवालय में पत्रकारों से कहा कि नोटिस मिलने पर मुख्य सचिव या गृह सचिव इसका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री से नई दिल्ली से आई उन रिपोर्टों के बारे में सवाल पूछा गया था जिसमें गृह मंत्रालय ने कुमार के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन करने पर कदम उठाने को कहा था। कुमार ने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के यहां धरने में शामिल होकर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया है। बनर्जी ने कहा, '' आज दोपहर ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कल होने वाले व्यापार सम्मेलन पर एक बैठक में मैंने मुख्य सचिव और गृह सचिव से पूछा था कि क्या इस तरह का कोई पत्र मिला है।'' बनर्जी ने मंगलवार को गृह मंत्रालय के इस आरोप को सरासर झूठ बताया था कि शहर के पुलिस प्रमुख ने उनके धरने में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा था कि अफसर कभी भी मंच पर नहीं आए थे।

वाड्रा से पूछताछ भारत के लोकतंत्र की सफलता का पैमाना : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ करने के मामले को भारत के लोकतंत्र की सफलता का पैमाना बताया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वाड्रा से पूछताछ के संबंध में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की इच्छाशक्ति की सफलता है कि एक नामचीन परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति को भी कानून के सामने पेश होना पड़ा। रविशंकर प्रसाद मीडिया को बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए फैसलों के बारे में बता रहे थे। प्रसाद ने कहा, यह भारतीय लोकतंत्र की सफलता का पैमाना है। वाड्रा पर हमला करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि संप्रग के शासनकाल के दौरान वाड्रा को पेट्रोल और रक्षा से जुड़े सौदों में रिश्वत मिली थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने 2008-2009 में संप्रग के शासनकाल में मिली रिश्वत से लंदन में आठ से नौ संपत्तियां खरीदी थीं। उन्होंने कहा कि वह वाड्रा से रोडपति से करोड़पति बनने का फॉर्मूला पूछना चाहेंगे। पात्रा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का कोर एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए कहा, हर कोई जानता है कि परिवार का हर सदस्य जमानत पर बाहर है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को वाड्रा से विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति रखने के सिलसिले में धन शोधन से जुड़े एक मामले में करीब साढ़े पांच घंटे पूछताछ की थी। इससे कुछ ही दिन पहले शहर की एक अदालत ने वाड्रा को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

पार्टी कार्यकर्ताओं को मुर्दाबाद के नारे लगाने से राहुल ने रोका, कहा- हताश हैं मोदी

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत के सामने झुके बिना ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा,''नरेंद्र मोदे के चेहरे पर हाव-भाव में बदलाव आया है। वह चारों तरफ से घिर गये हैं।''

राउरकेला।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि राफेल मुद्दे के बाद प्रधानमंत्री 'हताश' नजर आते हैं। ऐसे में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके राजनीतिक विरोधी के खिलाफ 'मुर्दाबाद' के नारे नहीं लगाने का आह्वान किया। यहां जनसभा के दौरान जब गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया तब कांग्रेस कार्यकर्ता एक सुर में 'मुर्दाबाद' चिल्लाने लगे। इस पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, ''ये शब्द (मुर्दाबाद) भाजपा/आरएसएस के लोग इस्तेमाल करते हैं। हम कांग्रेस वाले इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम प्रेम और स्नेह में विश्वास करते हैं।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत के सामने झुके बिना ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा,''नरेंद्र मोदे के चेहरे पर हाव-भाव में बदलाव आया है। वह चारों तरफ से घिर गये हैं।'' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''वह जहां कहीं भी देखते हैं उन्हें राफेल, किसान, मजदूर और महिलाएं नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी अब सभी से घिर गये हैं। उनके चेहरे पर, मूड और हाव-भाव में बदलाव आया है। हमने नफरत से ऐसा नहीं किया है। हमने प्यार से उनसे सवाल किया। हमने प्रेम के रास्ते से ऐसा किया। हम उन्हें हरायेंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि कांग्रेस ओड़िशा में बीजू जनता दल को भी हराने के लिए इसी प्यार का इस्तेमाल करेगी। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक स्थल पर स्थानीय आदिवासियों के साथ नृत्य किया।

खुशखबरी : असंगठित क्षेत्र के कामगारों का जल्द बनेगा पेंशन कार्ड

नई दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन के ऐलान के बाद से वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने मिलकर योजना की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। सूत्रों के जरिए मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सरकार इन कामगारों के लिए एक पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कार्ड जारी कर सकती है। इसके जरिये न सिर्फ उनके पेंशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बल्कि दूसरी उस कैटेगरी की दूसरी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजें भी मिल जाया करेंगी।

कैसे मिलेगी पेंशन

मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेंशन योजना का फायदा लेने वाले व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा। साथ ही उस बैंक अकाउंट का पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट भी देना होगा। पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का जिम्मा लाइफ इंश्योरेंश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंधों पर डालने की योजना है। हालांकि देशभर में एक साथ इस योजना लागू करने के दौरान शुरुआती दिनों में सभी बैंक शाखाओं और पोस्ट पेमेंट बैंक के काउंटर्स की भी मदद ली जा सकती है।

फर्जीवाड़ा रोकने के इंतजाम

योजना का फायदा कोई अपात्र व्यक्ति न उठा ले इसके लिए भी सरकार बाकायदा व्यवस्था बना रही है। कामगार के जरिये सेल्फ डिक्लेरेशन में दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर उसका अकाउंट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफधोखाधड़ी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अकाउंट आधार से जुड़ेगा

अकाउंट में दोहरीकरण से रोकने और सुरक्षा के लिहाज से मजबूत बनाने के मकसद से उस अकाउंट को आधार से भी जोड़ा जाएगा। इसी अकाउंट में व्यक्ति अपना योगदान देगा और उसी अनुपात में सरकार का भी योगदान रहेगा। स्कीम के अनुसार 18 वर्ष के कामगार को 55 रुपये महीने और 29 साल के व्यक्ति को 100 रुपये महीने की राशि जमा करनी होगी। इतनी ही राशि उसके खाते में सरकार की तरफ से आएगी। व्यक्ति के 60 साल के होने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। बाकी उम्र के लोगों के लिए उसी अनुपात में रकम घट या बढ़ सकती है।

योजना पर मंथन जारी

हालांकि अभी इस योजना में अभी मंथन का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरकार अभी इस बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि यदि व्यक्ति कुछ महीने अपना योगदान देने की स्थिति में नहीं रहता है तो उसकी पेंशन का क्या होगा और अकाउंट किन हालातों में चालू रखा जा सकेगा।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारा, पूछा- `आप कैसी सरकार चला रहे हैं'

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मामले को पटना से दिल्ली के साकेत कोर्ट स्थित स्पेशल पोक्सो कोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। कोर्ट इस मामले की प्रतिदिन सुनवाई करेगी।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट 6 महीने के अंदर इस मामले का निपटारा करे। वहीं, सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में अभी तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे एक सीबीआई ऑफिसर का ट्रांसफर बिना सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के कैसे किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ऐसी चीजों की इजाजत कैसे दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दो बजे तक सारे सवालों का जवाब देने के लिए भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बिहार सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप सरकार कैसे चला रहे हैं? फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि आप कुछ कठिन सवालों के लिए तैयार रहिए।

साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि पटना से दिल्ली दो घंटे का रास्ता है और हम सवाल-जवाब के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी यहां खड़ा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के वकील से कहा कि अगर आप सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं तो किसी अफसर को बुलाइए। अब बस बहुत हो गया है। इस मामले में शुरु से ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और बिहार सरकार को कई बार फटकार लगाई है। इस मामले के अंदर कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं इसलिए इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और गवाह भी इतनी दूर आएंगे तो निष्पक्ष गवाह देंगे।

शत्रुघ्न सिन्हा बोले, 'मैंने तमाम हरकतें कीं, लेकिन मेरा नाम मीटू आंदोलन में नहीं आया'

मुंबई ।

दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को कहा कि हर सफल व्यक्ति के पतन के पीछे एक महिला है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मीटू आंदोलन का मजाक नहीं बना रहे हैं और उनकी टिप्पणियों को सही भाव में लिया जाना चाहिए। लेखक ध्रुव सोमानी की पुस्तक 'ए टच ऑफ एविल' के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा, ''आज मीटू का समय है और कहने में कोई शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए कि सफल व्यक्ति के पतन के पीछे महिला है। मैंने इस आंदोलन में जो देखा है उसमें सफल पुरुषों की परेशानियों और बदनामी के पीछे ज्यादातर महिलाएं हैं।'' उन्होंने कहा, ''मैं वास्तव में खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि आज के समय में तमाम हरकतें करने के बावजूद मेरा नाम मीटू आंदोलन में नहीं आया। इसलिए, मैं अपनी पत्नी को सुनता हूं और कभी-कभार उसकी आड़ लेता हूं ताकि कुछ न हो तो भी मैं दिखा सकूं कि 'मैं खुशहाल शादीशुदा हूं, मेरा जीवन अच्छा है।'' सिन्हा ने कहा उनकी पत्नी पूनम एक 'देवी' हैं और उनका 'सबकुछ' है। उन्होंने कहा, ''यहां तक कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ कहना चाहता है तो कृपया नहीं कहें।'' पिछले साल हिन्दी फिल्म जगत में मीटू आंदोलन का प्रभाव रहा और यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार की खौफनाक कहानियों के साथ कई महिलाएं सामने आई थी।

योगी सरकार ने पेश किया बजट, मदरसों को मॉर्डन बनाने के लिए दिए 459 करोड़

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गुरुवार (07 फरवरी) को अपना तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल की तुलना में 12 फीसदी अधिक है। बजट पेश करने से पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट प्रस्ताव पास किया गया। बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। वित्त मंत्री ने राजेश अग्रवाल ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले प्रयागराज में चल रहे कुंभ का जिक्र किया। अवस्थापना के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस को शामिल किया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्प्रेस के लिए 1000 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, आगरा लखनऊ एक्प्रेस वे 6 लेन के लिए 100 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जबकि स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770 ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण के लिए 459 करोड़ की दिए हैं।

संस्कृति विभाग में मथुरा-वृंदावन के मध्य आडोटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ दिए गए हैं। वहीं, बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ पुष्टाहार के लिए, 4004 करोड़ आयुष्यमान भारत योजना के तहत 1298 करोड़ मंजूर किए, प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के तहत 291 करोड़, आयुष्यमान योजना से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री जानारोग्य अभियान के तहत 111 करोड़ का बजट दिया गया। पर्यटन विभाग के लिए बजट में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किए हैं। अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिए 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास के लिए 27 करोड़ की व्यवस्थ की गई है। पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए और प्रो-पुआर टूरिस्ट के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

संपादकीय

उजागर हुई पाक की असलियत

प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान का जो रुख सामने आता दिखा, उससे यह उम्मीद जरूर पैदा हुई थी कि संभवतः वे भारत के साथ संबंधों को एक नया आयाम देंगे। लेकिन व्यवहार में पाकिस्तान की ओर से की गई अवांछित हरकतों से ऐसा लगता नहीं है कि वह दोस्ताना रिश्तों को लेकर गंभीर है। पाक का दोगलापन एक बार फिर उजागर हुआ है। उसके विदेश मंत्री के हुर्रियत के प्रति प्रेम ने पाक की असलियत सामने ला दी है।

पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान का जो रुख सामने आता दिखा, उससे यह उम्मीद जरूर पैदा हुई थी कि संभवतः वे भारत के साथ संबंधों को एक नया आयाम देंगे। लेकिन व्यवहार में पाकिस्तान की ओर से की गई अवांछित हरकतों से ऐसा लगता नहीं है कि वह दोस्ताना रिश्तों को लेकर गंभीर है। वरना यह कैसे संभव हो पा रहा है कि कश्मीर में भारत अस्थिरता पैदा करने वाली तमाम ताकतों की जिस चुनौती से जूझ रहा है, पाकिस्तान को उनसे संबंध बनाए रखना जरूरी लगता है। जम्मू-कश्मीर की समस्या में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और उसके नेताओं का कैसा दखल है, इससे पाकिस्तान अनजान नहीं है। मगर वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक से टेलीफोन पर बात करने में कोई हिचक नहीं होती है। सवाल है कि अगर पाकिस्तान के शीर्ष स्तर के नेता की ओर से हुर्रियत के नेता को तरजीह देना भारत अपने आंतरिक मामलों में दखल मानता है तो पाकिस्तान को ऐसा करने का हक कहां से मिला है! इसमें दो राय नहीं कि ऐसा करके पाकिस्तान भारत की संप्रभुता में दखल देने जैसा काम कर रहा है। लेकिन क्या उसे यह उम्मीद है कि भारत को इसकी अनदेखी करनी चाहिए?

दुनिया का शायद ही कोई ऐसा आजाद और संप्रभु देश होगा जो कि अपनी एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के प्रति आंखें मूंदे रखेगा। इसलिए अगर भारत ने इसे अपनी संप्रभुता में दखल और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के 'शर्मनाक प्रयास' के रूप में देखा तो यह स्वाभाविक है। इसी सिलसिले में भारत ने बीते बुधवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद को तलब किया और इस मसले पर अपनी आपत्तियां दर्ज कीं। सच तो यह है कि इस तरह की हरकत खुद पाकिस्तान के अपने पैमानों के मुताबिक भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सभी नियमों का उल्लंघन है। इसलिए अगर कुरैशी की मीरवाइज से बातचीत को भारत के आंतरिक मामलों में सीधे दखल की तरह देखा जा रहा है तो यह स्वाभाविक है। बल्कि ऐसा करके पाक ने एक बार फिर यही दर्शाया है कि वह आतंकियों और भारत के खिलाफ होने वाली गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्वों को शह देता है। जबकि पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे इस राज्य से संबंधित किसी भी मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।

हालांकि, भारत की आपत्तियों को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है और कहा है कि उसकी कश्मीरी नेताओं से इस तरह की बातचीत हमेशा होती रही है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन क्या वह अपने सीमा-क्षेत्र में किसी अन्य देश के शीर्ष नेताओं के स्तर से ठीक इसी तरह की गतिविधि को लेकर ऐसे ही खयाल रख सकता है? यह छिपा नहीं है कि अपने सीमा-क्षेत्र में होने वाली आतंकी गतिविधियों के लिए पाक अक्सर भारत पर आरोप लगाता रहा है। जबकि लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तानी ठिकाने से अपनी गतिविधियां संचालित करने की खबरें अब नई नहीं हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में कई बार पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया जा चुका है। इसके अलावा, एक ओर पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ बातचीत की पेशकश करते हैं, दूसरी ओर उनकी सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री वहां के आतंकी सरगना हाफिज सईद के साथ मंच तक साझा करते दिखाई देते हैं तो एक अन्य मंत्री भारत में अलगाववादी तत्वों से बातचीत करते हैं। इस तरह के दोहरे रवैये के साथ पाकिस्तान किस बुनियाद पर भारत के साथ दोस्ती या फिर सकारात्मक रुख की उम्मीद करता है?

सच तो यह भी है कि भारत चाहे कितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। ऐसा उसके दोगलेपन की वजह से है। आतंकवाद की समस्या से भारत सदियों से जूझता नजर आ रहा है और आतंकवाद की समस्या की जड़ें कहां हैं यह किसी से छिपी नहीं है। भारत कितनी बार पाकिस्तान से सकारात्मक बातचीत कर चुका है और हर बार करने की पहल करता है लेकिन पाकिस्तान उसे गंभीरता से नहीं लेता। और तो और पाकिस्तान आए दिन भारत को गीदड़ भभकी भी देने से बाज नहीं आता। अगर उदाहरण देखें तो कुछ माह पहले दिल्ली में भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव सहित अनेक समस्याओं के निस्तारण के लिए डीजी स्तर की वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि दोनों देश सीमा पर संघर्ष विराम की स्थिति बहाल करेंगे। इतना ही नहीं इस बात की भी जरूरत महसूस की गई कि तमाम विवादित मसलों को हल करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता के दरवाजे खोलने चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रतिनिधिमंडल से यहां तक कहा कि भारतीय सुरक्षा बल सीमा पर पहले गोली नहीं चलाएंगे। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया।

एक तरह सहमति बनी थी कि सीजफायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और दूसरी सुबह ही पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ हुई जिसमें चार आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। इस घुसपैठ में दो जवान शहीद हो गए थे। यह पाकिस्तान का दोगलापन ही है कि एक तरफ वार्ता कर रहे है दूसरी तरफ फायरिंग की जा रही है। भारत तो हमेशा ही सकारात्मक कदम उठाया है, लेकिन पाकिस्तान कभी इस मुद्दे को लेकर सकारात्मक नहीं दिखा। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में दो बार भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत की कोशिश हुई लेकिन पाकिस्तान के अडियल रवैये की वजह से ऐन वक्त पर वार्ता रद्द करनी पड़ी। दरअसल सच्चाई यह है कि पाकिस्तान सीमा पर शांति चाहता ही नहीं है। जब सीमा पर तनाव व्याप्त रहेगा तो भारत में भी अस्थिरता बनी ही रहेगी। पाकिस्तान भारत को जानबूझकर परेशान करता रहा है। चाहे सीज फायर का उल्लंघन करके या आतंकवाद का सहारा लेकर। जब एनडीए सरकार का गठन हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था। इससे पूरे विश्व में एक सकारात्मक संदेश गया और उम्मीद जगी कि शायद दोनों देशों के आपसी संबंध सुधरेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सार्क सम्मेलन में भी उम्मीद जगी थी कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत होगी लेकिन नतीजा सिफर रहा।

उफा में भी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच अनेक मुद्दों पर लंबी और सकारात्मक बातचीत हुई। बात आगे भी बढ़ी लेकिन दूर तक नहीं गई। और भविष्य में भी ऐसा होता दिख नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले ही करतारपुर कॉरीडोर के लिए भारत सरकार के सुझाव को स्वीकार कर चर्चा में आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने को तैयार होने की बात भी कही और आंतकी हाफिज तथा दाऊद पर कहा था कि यह हमें विरासत में मिले हैं तथा हमें अतीत को किनारे कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कश्मीर मसले को ले इमरान ने कहा कि इसका सैन्य समाधान नहीं हो सकता। इमरान खान द्वारा पिछले 100 दिनों के बीच भारत के साथ संबंध सुधारने के मामले में जो कुछ कहा गया उसे भारत सीमा से आगे स्वीकार करने को तैयार नहीं था क्योंकि अतीत में भी पाक अपने रंग समय-समय पर बदलता रहा है। भारत उसके अतीत को देखते हुए सतर्क हो चल रहा था तथा कह रहा था कि इमरान कुछ सकारात्मक कदम उठाकर दिखाएं। भारत जिस बात को लेकर इमरान सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा किए गए कृत्य से जग जाहिर हो गया है।

अनिल निगम
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

विचार

ममता को धरने से क्या मिला?

शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई पूछताछ को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक ड्रामा अभी भले ही खत्म हो गया हो, पर इसके नफा-नुकसान को लेकर आकलन शुरू हो गया है। सवाल यह भी है कि ममता को इससे क्या मिला और अब भाजपा इसे किस तरह से भुनाएगी।

आठ फरवरी तक चलने वाला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना अफरा-तफरी में तीन दिन पहले ही खत्म करना पड़ा। महागठबंधन के इकलौते प्रतिनिधि के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ही उस वक्त ममता के साथ खड़े दिखे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही यह लगने लगा था कि अब ममता बनर्जी को हथियार डालना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के समर्थन में अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रातोंरात धरने पर बैठकर और सीबीआई से जंग के सवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी नाराजगी को इस तरह जाहिर करके ममता ने क्या खोया और क्या पाया? क्या ममता के इस कदम से महागठबंधन मजबूत हुआ या फिर इस सवाल पर उसमें और दरार नजर आ गई? क्या इस धरने और ममता के गुस्से भरे तेवर ने भाजपा की बंगाल में बढ़ती लोकप्रियता को कम किया या उसे और बढ़ा दिया?

यह जानते हुए भी कि चुनावी वक्त में तमाम भाजपा विरोधी नेताओं से जुड़े सारे मामले और तेजी से खुलेंगे व शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर जिस तरह की राजनीति चलती रही है, वह और मुखर होगी, ममता ने खुलकर राजीव कुमार का साथ क्यों दिया, ये सारे सवाल अब हर खेमे में गंभीरता से उठाए जाने लगे हैं। तो क्या ममता बनर्जी सचमुच अपने राज्य में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता और रैलियों में जुटने वाली जबरदस्त भीड़ से घबरा गई हैं या फिर इस बहाने दो दिनों तक लगातार मीडिया पर छाकर उन्होंने जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की वह आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में कोई बदलाव ला भी सकता है? अगर टीवी चैनलों पर लगातार दो दिनों तक इस बारे में बहसें सुनी हों, तो साफ हो जाता है कि इतनी जबरदस्त कवरेज के बावजूद ममता भाजपा के खिलाफ वो माहौल नहीं बना पाईं, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेशी का हुक्म दिया और उनपर जांच से भागने के आरोप लगे।

दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने शारदा चिटफंड घोटाले के बारे में बार-बार सफाइयां पेश कीं, लेकिन राजीव कुमार के पक्ष में मजबूत दलीलें नहीं पेश कर पाई, उससे कहीं न कहीं सीएम ममता बनर्जी का आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगाया है। जाहिर है, अब इस स्थिति का फायदा भाजपा हर तरीके से उठाने वाली है और अपनी आगामी रैलियों में ममता और महागठबंधन के नेताओं के खिलाफ माहौल बनाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन यह भी सही है कि इस पूरे मामले में अगर सबसे ज्यादा किसी की विश्वसनीयता और राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठे हैं तो वह है सीबीआई और कोलकाता पुलिस, जिस तरह दोनों के बीच टकराव को लेकर सियासत हुई, उससे इतना तो साफ हो गया कि सीबीआई की इस कार्रवाई को चुनावी चश्मे से ही देखा जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि अब भाजपा और ममता का अगला कदम क्या होगा।

स्त्री-पुरुष अनुपात सुधारना होगा

देश के महापंजीयक कार्यालय की ओर से जारी-2016 की नागरिक पंजीकरण प्रणाली के मुताबिक दक्षिण भारतीय राज्यों में स्त्री-पुरुष के बीच अनुपात की खाई चौड़ी हो रही है। अगर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या में संतोषजनक संतुलन नहीं बन पा रहा है, तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? एक समय दक्षिण भारत के राज्यों से सीख लेने की बात कही जाती रही है, मगर वहां भी अब हालात बिगड़ रहे हैं।

देश में स्त्री-पुरुष अनुपात को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। अब तक इस मसले पर अमूमन उत्तर भारत के राज्यों को कठघरे में खड़ा पाया जाता रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों में स्त्री-पुरुष अनुपात का आंकड़ा काफी अच्छी स्थिति में रहा है। पर एक नए आंकड़े के मुताबिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में उभरी तस्वीर चिंताजनक है। देश के महापंजीयक कार्यालय की ओर से जारी-2016 की नागरिक पंजीकरण प्रणाली के मुताबिक पिछले कुछ सालों के दौरान इन राज्यों में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में बढ़ रही इस असमानता पर चिंता जताई है। इस पर आधारित खबर का संज्ञान लेते हुए आयोग ने केंद्रीय महिला और बाल कल्याण विभाग के सचिव और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग का यह सवाल सही है कि अगर दक्षिण के विकसित राज्यों में भी स्त्रियों की तादाद में कमी आ रही है तो फिर महिलाओं के कल्याण के लिए जारी योजनाओं पर अमल की क्या स्थिति है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने बालिकाओं के संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना विकसित करने के कई प्रयास किए हैं और इसके लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' जैसे अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है। लेकिन इसके बरक्स अगर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या में संतोषजनक संतुलन नहीं बन पा रहा है, तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? इस गहराती समस्या पर बात करते हुए उत्तर भारत के राज्यों को दक्षिण भारत के राज्यों से सीख लेने की बात कही जाती रही है, जहां स्त्री और पुरुष अनुपात न केवल संतोषजनक रहा है, बल्कि कई हिस्सों में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कुछ ज्यादा भी दर्ज की गई थी। हालत यह है कि आंध्र प्रदेश में 2016 में प्रति एक हजार लड़कों के मुकाबले महज आठ सौ छह लड़कियों का जन्म दर्ज किया गया। यह आंकड़ा सबसे निम्न स्तर पर मौजूद राजस्थान के बराबर है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी तस्वीर बहुत बेहतर नहीं है।

सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों के दौरान आखिर क्या और किस तरह का बदलाव आया है, जिसमें अकेले केरल को छोड़ कर दक्षिण भारत के राज्यों में भी लड़कियों को जन्म देने और उनके संरक्षण के प्रति समाज का रुख इस कदर नकारात्मक हो गया? इस मसले पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि पिछले कुछ सालों के दौरान दक्षिण के राज्यों में भी जिस तरह गर्भावस्था में लिंग जांच कराने की प्रवृत्ति है, वह बेहद चिंताजनक है। इसके लिए मुख्य रूप से इस तरह की जांच को आसान बनाने वाली आधुनिक मशीनों की उपलब्धता ही जिम्मेदार है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो समाज बेटियों के जीवन को लेकर जागरूक रहा है, वह मशीनों की आसान उपलब्धता के बाद सोच के स्तर पर इतना प्रतिगामी हो रहा है। क्या सरकार और प्रशासन का तंत्र इस कदर कमजोर है कि वह गर्भावस्था में लिंग जांच करने वाले क्लिनिकों या फिर अस्पतालों पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है? जाहिर है, अब समाज में लैंगिक समानता की चेतना का विकास करने के साथ-साथ गर्भ में भ्रूण की जांच करने वालों के खिलाफ अगर तुरंत सख्ती नहीं की गई, तो आने वाले समय में तस्वीर और ज्यादा चिंता करने लायक हो जाए।

कहा जाता है कि अपनी युवा जनसंख्या के बूते पर भारत के पास अगले तीन दशकों में तरक्की की कुलांचे भरने का मौका है। आज दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार किया जाने वाला भारत तीन दशक बाद युवा नहीं रहेगा। जनसंख्या उम्रदराज होनी शुरू होगी, तो उत्पादकता घटेगी। उत्पादकता घटेगी, तो अगले तीन दशकों में हुई तरक्की पर भी लगाम लगेगी और कुछ सालों के लिए एक ठहराव आ जाएगा। उस ठहराव को फिर गतिशील बनाना तब के हालात पर निर्भर होगा। फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश को युवा ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यह तभी संभव है, जब इसमें सभी युवा योगदान दें। युवक भी, युवतियां भी और ऐसा तभी हो सकेगा जब युवतियों के सामने कोई डर न हो- वे निर्भय होकर काम कर सकें। समाज और देश की तरक्की के लिए फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने की है। ऐसे अपराधों के लिए अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं- समाज की पुरुषवादी सोच, महिलाओं को कमतर आंकना, महिलाओं का आत्मनिर्भर न होना, महिलाओं को दूसरे दर्जे का मानने की पुरातन सोच यह सूची काफी लंबी हो सकती है। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण वजह जनसांख्यिकी भी हो सकती है। एक सर्वे में पाया गया है कि जिन समाजों और देशों में स्त्री-पुरुष अनुपात सही है, वहां महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होती है और उनके खिलाफ अपराध कम होते हैं। इसके विपरीत, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का कम होना महिलाओं के खिलाफ अपराधों की वजह है।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 940 महिलाएं हैं। 28 राज्यों व सात केंद्रशासित प्रदेशों में से 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल (1084) पुडुचेरी (1038), तमिलनाडु (995), आंध्रप्रदेश (992), छत्तीसगढ़ (991), मणिपुर (987), मेघालय (986), ओडिशा (974), गोवा (968), कर्नाटक (968), उत्तराखंड (963), त्रिपुरा (961), असम (954), पश्चिम बंगाल (947), झारखंड (947), महाराष्ट्र (946) और लक्षद्वीप (946) में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत 940 से बेहतर है। वहीं, 16 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों नागालैंड (931), मध्यप्रदेश (930), राजस्थान (926), अरुणाचल प्रदेश (920), गुजरात (918), बिहार (916), उत्तर प्रदेश (908), पंजाब (893), सिक्किम (889), जम्मू-कश्मीर (883), अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (878), हरियाणा (877), दिल्ली (866), चंडीगढ़ (818), दादर व नागर हवेली (775) और दमन व दीव (618) में स्त्री-पुरुष अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। 2001 की जनगणना में देश में स्त्री-पुरुष अनुपात 933-1000 था। यानी अगले 10 साल में प्रति हजार पुरुषों पर 7 स्त्रियां बढ़ीं। यह अच्छी खबर जरूर है, मगर अंतर अब भी काफी (60) है।

भारत में केवल केरल और पुडुचेरी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। अगर पूरी दुनिया पर नजर डालें, तो कुल 118 देशों जिनमें जिम्बाब्वे, वियतनाम, वेनेजुएला, उजबेकिस्तान, उरुग्वे, यूक्रेन, टुवालु, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, तंजानिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्वाजीलैंड, सूरीनाम, सर्बिया, सेनेगल, साओ तेत्मे एंड प्रिंसिप, सैन मैरिनो, सेंट मार्टिन, सेंट लुशिया, सेंट किट्स ऐंड नेविस, रवांडा जैसे देश हैं, वहां भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। ये देश सभी महाद्वीपों के हैं। विकसित और विकासशील, हर तरह के हैं। इनमें से ज्यादातर देशों में महिलाओं के खिलाफ भारत से कम अपराध होते हैं, क्योंकि वहां कन्याओं को बोझ नहीं माना जाता और कन्या भ्रूण हत्याएं नहीं होतीं। महिलाओं के प्रति आपराधिक नजरिया यहीं से शुरू होता है। ये सारे देश हमारे लिए उदाहरण हैं। हम इनसे कुछ सीखकर स्त्री-पुरुष के अनुपात को साधने में सफल हो सकते हैं।

कविता श्रीमाली
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

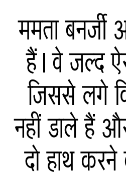

पुलिस कमिश्नर के बचाव में ममता बनर्जी ने जिस तरह से कवच का काम किया, उसे पूरे देश ने देखा। विपक्ष की मनमानी भी सभी के सामने आ गई है।

संबित पात्रा, भाजपा प्रवक्ता

ममता बनर्जी अभी शांत नहीं हुई हैं। वे जल्द ऐसा कदम उठाएंगी जिससे लगे कि उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं और सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं।

विजय विद्राही, वरिष्ठ पत्रकार

सत्यार्थ

पैस्टोला का अनाथ प्रेम

ऑस्ट्रिया का एक पैस्टोला नाम का छात्र डॉक्टरी पढ़ रहा था। उसके मन में बचपन से ही डॉक्टर बनने की तमन्ना थी। एक दिन जब वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बच्चा मिला। बच्चे को अकेला देख पैस्टोला ने उसे अपने साथ ले लिया। उसने बच्चे के अभिभावकों को खोजने के लिए पुलिस में सूचना दी। जब उस बच्चे के अभिभावकों का पता न चला तो पैस्टोला ने उसे अनाथालय में दे दिया। लेकिन उसे उस बच्चे से बेहद लगाव हो गया था। इसलिए वह अकसर उसे अनाथालय में देखने आता। पैस्टोला ने देखा कि वहां बच्चों की शिक्षा और निर्वाह की व्यवस्था तो है, पर कर्मचारियों में दयाभाव नहीं है। इसलिए बच्चे ठीक से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। यह जानकर पैस्टोला ने आंदोलन चलाया कि जिनकी छोटी गृहस्थी है या जो निसंतान हैं, वे अनाथ बच्चों को गोद लें। इस आंदोलन का लोगों पर असर हुआ। कई उदार, धनी व शिक्षित लोगों ने ऐसे बच्चों को अपने परिवार में शामिल कर लिया। आत्मीयता एवं अपनत्व भरे माहौल में बच्चों का विकास होने लगा। पैस्टोला ने उन अनाथ बच्चों की देखरेख में अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने सदैव अनाथ बच्चों में ही अपने बच्चों की छवि देखी। उन्होंने असहाय व्यक्तियों, विधवाओं और वृद्धाओं की भी मदद की। अपनी आमदनी भी वे ऐसे ही व्यक्तियों व बच्चों पर लगा देते। पैस्टोला का यह आंदोलन दूर-दूर तक फैल गया। उन्हें उनके इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपनी पुरस्कार की राशि भी उन्होंने इसी प्रयोजन में लगा दी। आज भी ऑस्ट्रिया के लोग पैस्टोला के उस आंदोलन की राह पर चल रहे हैं एवं कई अनाथालयों व असहायों की मदद कर रहे हैं।

रेनू सैनी

सार समाचार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर,कहा- ज्यादा संख्या में आए प्रवासी

वाशिंगटन। प्रवासियों पर अपने कड़े रूख में नरमी लाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वह ज्यादा संख्या में वैध प्रवासियों के देश में आने के पक्ष में हैं क्योंकि उनसे देश को आर्थिक लाभ होता है। ट्रंप ने अपने वार्षिक संबोधन में भी कहा था कि वे चाहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनके देश आएं लेकिन उन्हें कानूनी रूप से आना होगा। हालांकि अभी तक उनकी नीतियों में यह परिलक्षित नहीं हो रहा है। स्थानीय संवाददाताओं ने उनसे प्रश्न किया कि क्या उनके वक्तव्य को नीति में बदलाव के तौर पर देखा जाए। इसके उत्तर में ट्रंप में कहा कि बदलाव है। लूसियाना के समाचार पत्र 'द एडवोकेट में एक संवाददाता ने ट्वीट किया। इसमें ट्रंप के हवाले से कहा गया, 'मैं चाहता हूं कि और लोग आए क्योंकि हमें फैक्ट्री और उद्योगों को चलाने के लिए तथा कंपनियां के संचालन के लिए लोगों की जरूरत है।

श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन के लिए संसदीय चर्चा स्थगित

कोलंबो। श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन के एक प्रस्ताव पर संसदीय चर्चा को गुरुवार को सरकार द्वारा एक प्रस्ताव वापस लेने के बाद टाल दिया गया। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा था कि वो ऐसे किसी कदम का विरोध करेंगे। युनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) महासचिव अकिला विराज कारियवासम ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार के गठन पर मंजूरी के लिये संसद में रखे गए प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा, 'प्रस्ताव को आज पेश नहीं किया जाएगा।' यह प्रस्ताव अगर पारित होता तो इससे प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में सक्षम होते और उससे भी महत्वपूर्ण वह साधारण बहुमत सुरक्षित कर लेते। संविधान के 19वें संशोधन के मुताबिक विक्रमसिंघे को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 30 तक ही सिमित रखनी होगी। वह उसी स्थिति में मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं जब वह किसी दूसरे दल के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय सरकार बनाएं।

दलित लेखक तेलतुम्बड़े की गिरफ्तारी का येल, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसरों ने किया विरोध

वाशिंगटन। हाल ही में हिरासत में लिए गए दलित लेखक आनंद तेलतुम्बड़े का समर्थन करते हुए अमेरिका और यूरोप के 600 से अधिक विद्वानों ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी कर भारत और महाराष्ट्र सरकार से तुरंत ऐसी कार्रवाइयां बंद करने का अनुरोध किया है.

तेलतुम्बड़े के खिलाफ फर्जी आरोपों का विरोध करते हुए बुधवार को जारी इस बयान में तेलतुम्बड़े की तुरंत गिरफ्तारी के खतरे की कड़ी आलोचना की गई है. साथ ही उन्हें विशिष्ट विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और देश के बुद्धिजीवियों में से एक बताया गया है.

बयान में कहा गया है कि वह दलित समुदाय के महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक हैं और उनकी लेखनी का लोकतंत्र, वैश्विकरण और सामाजिक न्याय जैसे विषयों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

प्रिंसटन, हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सहित विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के विद्वानों के संयुक्त मंच इंडियन सिविल वाच (आईसीडब्ल्यू) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र पुलिस ने 28 अगस्त, 2018 को गैर-कानूनी तरीके से तेलतुम्बड़े के मकान की तलाशी ली थी.

उसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र सरकारों ने साथ मिलकर डॉक्टर तेलतुम्बड़े के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए और उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार करने की धमकी दी. इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार निलंबित हो जाता है और उसे अनिश्चित काल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है.

आतंकवादी संगठन आईएस का खात्मा कर दिया गया है : ट्रंप

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आतंकवादी संगठन आईएस का खात्मा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संभवतः अगले सप्ताह वह किसी भी समय आईएस को उसके कब्जे वाले क्षेत्रों से 100 फीसदी तक खदेड़ने की औपचारिक घोषणा करेंगे। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी सेना, उसकी गठबंधन सहयोगी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने सीरिया और इराक में पहले आईएस के कब्जे में रहे पूरे क्षेत्र को लगभग आजाद करा लिया है। ट्रंप ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा, ''संभवतः अगले सप्ताह यह घोषणा की जाएगी कि हमने आईएस के क्षेत्र पर 100 फीसदी तक नियंत्रण कर लिया है लेकिन मैं आधकारिक बयान का इंतजार करना चाहता हूं। मैं जल्दबाजी में यह नहीं कहना चाहता।''

उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन के नए रुख के कारण मैदान पर अमेरिकी कमांडर और गठबंधन के सहयोगी सशक्त हुए और उन्होंने सीधे आईएस की ''दुष्ट'' विचारधारा का सामना किया। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 20,000 वर्ग मील से अधिक भूमि पर फिर से कब्जा जमाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ''हमने युद्ध का एक मैदान जीता और उसके बाद जीतते चले गए और मोसुल तथा रक्का दोनों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया।'' उन्होंने कहा, ''आईएस के सौ से ज्यादा अन्य शीर्ष अधिकारियों का खात्मा किया गया और हजारों आईएस लड़ाकों को खदेड़ दिया।''

ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने खूंखार आतंकवादियों के चंगुल से 50 लाख से ज्यादा नागरिकों को रिहा कराया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष एक साझा लड़ाई है। उन्होंने कहा, ''हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़ते तो कभी आज जैसी स्थिति नहीं हो सकती थी। हर किसी को अपनी भूमिका अदा करनी है और अपना योगदान देना है।''

ब्रेग्जिट समझौते पर फिर से बातचीत के लिए टेरीजा मे ब्रसेल्स पहुंची

ब्रसेल्स। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने बृहस्पतिवार को ब्रेग्जिट समझौते पर यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बातचीत पुनः शुरू कर दी और वह इस बारे में यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीखे टकराव के लिए भी तैयार हैं। टेरीजा मे का स्वागत यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ज्यां क्लाउड जंकेर ने किया। उनके स्वागत के लिए आयोजित समारोह के माहौल से ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के बीच तनाव साफ नजर आ रहा था।

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की तारीख 29 मार्च तय की गई थी जो करीब आ रही है। समझा जा रहा है कि वापसी संबंधी कानूनी समझौते पर फिर से बातचीत शुरू होने पर यूरोपीय संघ के अधिकारियों के कड़े सवालों का टेरीजा को सामना करना पड़ेगा। इस समझौते को ब्रिटिश संसद ने खारिज कर दिया था लेकिन इससे पहले समझौते की पुष्टि की जा चुकी थी।

दोनों पक्षों के बीच दरार पहले ही कम नहीं थी। उस पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने बुधवार को यह कह कर कड़वाहट गहरी कर दी कि ब्रेग्जिट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी न होने के बावजूद इसका जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके लिए शायद ''नर्क में खास जगह'' आरक्षित होगी। टेरीजा और टस्क की बातचीत से पहले, कैमरे के सामने होने वाला उनका सार्वजनिक अभिनंदन अचानक ही रद्द कर दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा अभी भी 585 पृष्ठों के वापसी समझौते में बदलाव चाहेंगी लेकिन यूरोपीय संघ के 27 अन्य नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। टेरीजा जोर देती हैं कि ''वैकल्पिक व्यवस्था'' की जा सकती है लेकिन यूरोपीय संघ के अधिकारी लंदन से स्पष्ट व्याख्या का इंतजार कर रहे हैं।

पाकिस्तान ने फेसबुक को अपना कायार्लय खोलने के लिए किया आमंत्रित

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को यहां अपना कार्यालय खोलने के लिए आमंत्रित किया है। हुसैन ने कल यहां' डिजीटल मीडिया के महत्व' पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश में विज्ञापन उद्योग की सालाना आमदनी सात अरब रूपए की है और सरकार ने अपने एक तिहाई विज्ञापन डिजीटल मीडिया को दे दिए हैं।

उन्होंने कहा कि विज्ञापनों का दायरा अब पारंपरिक मीडिया से

हट कर कर डिजीटल मीडिया की तरफ जा रहा है और यह पारंपरिक मीडिया के लिए एक बड़ा संकट है। यदि इस संकट से निपटना है तो मीडिया में आधुनिक तकनीक को अपनाना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तानी पेशवर अभी भी तकनीक से अधिक परिचित नहीं है।

उन्होंने मीडिया जगत से इस बात पर शोध करने का आग्रह किया कि पारंपरिक मीडिया पर डिजीटल मीडिया का क्या और कितना असर हो रहा है।

हुसैन ने कहा कि सरकार ने 'एसोसिएटिड प्रेस ऑफ पाकिस्तान 'को 'डिजीटल सर्विस ऑफ पाकिस्तान' में परिवर्तित करने का फैसला किया है और सरकार इस पर 85 करोड़ रूपए खर्च कर रही है लेकिन यह भारी बिडंबना है कि इसके अधिकतर कर्मचारियों को ई-मेल अकाउँट आपरेट करना ही नहीं आता है।

उन्होंने कहा कि सरकार बेव टीवी, सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नए दिशा निदेर्श लाएगी।

तुलसी गबार्ड ने कहा, 'सीरियाई राष्ट्रपति असद अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं'

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दावेदारी की आकांक्षी और पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति बसर अल-असद अमेरिका के 'दुश्मन नहीं' हैं और युद्ध प्रभावित यह देश अमेरिका के लिए कोई 'प्रत्यक्ष' खतरा पैदा नहीं करता.

डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 2020 में राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए हाल में अपना अभियान शुरू करने वाली 37 वर्षीय गबार्ड की पूर्व में 2017 में असद से मुलाकात के लिए आलोचना हो चुकी है. सीरियाई नेता पर वहां चल रहे गृहयुद्ध के दौरान हजारों सीरियाई नागरिकों की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप है.

हवाई से प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित गबार्ड ने बुधवार को एमएसएनबीसी से कहा %असद अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं क्योंकि सीरिया अमेरिका के लिये सीधे तौर पर कोई खतरा पैदा नहीं करता.%

जब उनसे पूछा गया कि करीब पांच वर्षों तक चले

गृहयुद्ध के दौरान अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोपी असद क्या अमेरिका के शत्रु हैं, गबार्ड ने कहा, 'आप इसकी जैसे चाहें वैसे व्याख्या कर सकते हैं.' उन्होंने कहा, 'मेरा कहना है कि चाहे यह सीरिया हो या कोई दूसरा देश, हमें यह देखने की जरूरत है कि कैसे उनके हित हमारे हितों से जुड़े हैं या उनके विपरीत हैं.'

ट्रंप ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए डेविड माल्पास को किया नामांकित

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के तौर पर वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डेविड माल्पास को नामांकित किया है। अगर विश्व बैंक समूह के निदेशक उनके पक्ष में मतदान करते हैं तो वह विश्व बैंक के अध्यक्ष के तौर पर जिम योंग किम का स्थान लेंगे। इस पद पर आम तौर पर अमेरिकी नागरिक ही आसीन होते आए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक का पद यूरोप के लिए है। विश्व बैंक में विभिन्न देशों के वोट को ध्यान में रखते हुए माल्पास के नाम की पुष्टि महज एक औपचारिकता है।

ट्रंप ने बुधवार को माल्पास के नामांकन की घोषणा करते हुए उन्हें ''विशेष व्यक्ति'' और ऐसा व्यक्ति बताया जो इस पद के लिए एकदम योग्य है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए वित्त अपर सचिव के तौर पर 62 वर्षीय माल्पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का कामकाज देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रख्यात अर्थशास्त्री माल्पास के पास अर्थशास्त्र, वित्त, सरकार और विदेश नीति में 40 साल का अनुभव है।

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस से अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में डिग्री पाने के बाद माल्पास ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में उप सहायक वित्त मंत्री और राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में उप सहायक विदेश मंत्री के पद पर काम किया। ट्रंप ने कहा, ''द वाल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक संपादकीय में कहा कि डेविड माल्पास बेहतरीन पसंद है। अमेरिका विश्व बैंक में सबसे अधिक योगदान देता है। वह उसे हर साल एक अरब डॉलर की धनराशि देता है।''

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि माल्पास लंबे समय से विश्व बैंक में जवाबदेही के कड़े समर्थक रहे हैं। वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने कहा कि ट्रंप ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के तौर पर माल्पास को नामांकित कर बेहतरीन व्यक्ति चुना है। चयन प्रक्रिया में ट्रंप की बेटी और वरिष्ठ राष्ट्रपति सलाहकार इवांका ट्रंप ने म्नुचिन की मदद की। इवांका ट्रंप ने कहा, ''विश्व बैंक की चुनौतियों और अवसरों के बारे में डेविड की व्यापक जानकारी उन्हें इस महान संस्थान का योग्य प्रबंधक बनाता है।

वित्त मंत्रालय में अपने दो साल के कार्यकाल में माल्पास ने बड़े विकास ऋणदाताओं को बेकार और अप्रभावी बताते हुए आलोचना की और सुधारों की अपील की। अब जब वह विश्व बैंक की विरासत संभालने वाले है तो वहां वह अपनी नीतियों की छाप छोड़ सकते हैं। उन्होंने साल 2017 में कांग्रेस के समक्ष गवाही में कहा था कि विश्व बैंक जैसे संस्थान बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन वे बहुत प्रभावशाली नहीं हैं। उन्होंने कहा था, ''वे अक्सर ऋण देने की प्रक्रिया में भ्रष्ट होते हैं और वे देशों के उन लोगों को लाभ नहीं देते जिन्हें वास्तव में उसकी जरुरत होती है।''

भारतीय अमेरिकी सिख गुरिंदर ने चुनावी राजनीति में आने की घोषणा की

वाशिंगटन (एजेंसी)।

प्रतिष्ठित रोजा पार्क्स ट्रेलब्लेजर पुरस्कार पाने के कुछ सप्ताह बाद प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी सिख गुरिंदर सिंह खालसा ने चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला किया है। सिंह ने सिटी काउंसिल ऑफ फिशर्स के चुनाव के लिए अपनी योजना की घोषणा करने के बाद बुधवार को इंडियानापोलिस में अपने समर्थकों से कहा, ''अपने समुदाय के लिए कुछ करने की इच्छा के साथ मेरे पूर्व अनुभवों पर आधारित सार्वजनिक नीति में रुचि उन कारणों में शामिल है जिससे मैंने चुनावी राजनीति में आने का फैसला किया।''

एक से ज्यादा दशक से इंडियाना में फिशर्स समुदाय के निवासी खालसा एक प्रतिष्ठित कारोबारी नेता, उद्यमी और परोपकारी है जिन्होंने राज्य और देश में जन सेवा के नेताओं और संगठनों के साथ काम किया। बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा, ''मैं जन सेवा के जरिए समाज को कुछ वापस करने का हिस्सा बनना चाहता हूं।'' गौरतलब है कि गत महीने खालसा को मई 2007 में दिखाए गए उनके साहस के लिए प्रतिष्ठित रोजा पार्क्स ट्रेलब्लेजर पुरस्कार के लिए चुना गया था। मई 2007 में उन्हें न्यूयॉर्क में एक विमान में चढ़ते हुए अपनी पगड़ी हटाने के लिए कहा गया था। इस घटना के बाद उन्होंने इस मुद्दे की ओर अमेरिकी संसद का ध्यान खींचा जिसके बाद देशभर में हवाईअड्डों पर पगड़ी उतारने की नीतियां बदली गई।

फर्जी विश्वविद्यालय के स्टिंग ऑपरेशन का अमेरिकी विधि विशेषज्ञों ने मांगा पूरा ब्यौरा

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में प्रख्यात वकीलों के एक द्विदलीय समूह ने अमेरिकी आतंरिक सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए उस स्टिंग ऑपरेशन का बुधवार को विस्तृत ब्यौरा मांगा जिसके बाद भारत के कम से कम 129 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पिछले माह कई छापों के बाद संघीय अधिकारियों ने 130 छात्रों को गिरफ्तार किया जिनमें 129 भारतीय हैं। ये छात्र मेट्रो डेट्रॉयट इलाके में कथित फर्जी विश्वविद्यालय में पंजीकृत थे। सांसदों ने पत्र में आतंरिक घरेलू सुरक्षा विभाग (डीएचएस) और अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि हालिया स्टिंग ऑपरेशन के बाद हिरासत में लेकर मिशिगन में रखे गए इन छात्रों के साथ उचित व्यवहार किया जाए, वकील की सुविधा सहित कानून के तहत प्रदत्त सभी अधिकार उन्हें दिए जाएं और पात्र छात्रों को मुचलके पर रिहा किया जाए।

कृष्णमूर्ति के साथ साथ कांग्रेस सदस्यों थॉमस सौजी, रॉब वूडल और ब्रेंडा लॉरेन्स ने पत्र में डीएचएस और आईसीई से यह भी कहा है कि वे भारतीय छात्रों के बारे में अद्यतन जानकारी भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावासों के साथ साझा करें तथा बंदियों की मुलाकात वाणिज्य दूत से भी कराने का प्रबंध करें। सांसदों ने आतंरिक सुरक्षा जांच द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन पर चिंता जाहिर की है। इस ऑपरेशन में एचएसआई के विशेष एजेंटों ने एक फर्जी विश्वविद्यालय ''यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर्मिंगटन'' चलाया जिसका उद्देश्य आव्रजन संबंधी जालसाजी में लिप्त चयनकर्ताओं और विदेशी छात्रों का पता लगाना था।

आईसीई के अनुसार, यह जांच 2015 में शुरू हुई और एचएसआई एजेंटों ने 2017 से फर्जी स्कूल संचालित किया। पिछले सप्ताह हुए खुलासे के अनुसार, स्कूल के लिए आठ व्यक्ति चयनकर्ता थे जिन्होंने सैकड़ों विदेशी नागरिकों को यूनिवर्सिटी के छात्रों के तौर पर पंजीकृत किया। इन आठों व्यक्तियों पर पूर्वी जिले मिशिगन के अमेरिकी अटॉर्नी ने वीजा जालसाजी करने और लाभ के लिए विदेशियों को प्रश्रय देने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। सांसदों ने कहा ''भारतीय अमेरिकी समुदाय और भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इन बंदी विदेशी नागरिकों के साथ किए जा रहे सलूक को लेकर चिंता जाहिर की है।''

भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और अमेरिका का मित्र बताते हुए पत्र में कहा गया है कि 2017 में देश भर में मौजूद 1,86,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या 17.3 फीसदी थी। आगे पत्र में कहा गया है कि ये छात्र दोनों देशों के बीच जनसंपर्क का अहम स्तंभ हैं और ये लोग गुणवत्ता के आधार पर अमेरिका आते हैं। ''दोनों देशों के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभकारी शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम संबंधी सहयोग को जारी रखने की भावना के तहत हम आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इस मामले से संबद्ध छात्रों के साथ नियमों के अनुरूप, ईमानदारीपूर्वक, मानवीय सलूक किया जाए।''

भारत, चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे जाने पर अमेरिकी सांसदों ने दिया यह प्रस्ताव

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

ढांचागत संरचनाओं पर निवेश के मामले में भारत एवं चीन के अमेरिका से आगे निकल जाने पर गौर करते हुए देश के दो शीर्ष सांसदों ने नयी परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुगम बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया. जॉन कोर्निन एवं मार्क वार्नर ने बुधवार को बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेवरेजिंग डेवलपमेंट (बिल्ड) प्रस्ताव पेश किया. जिसका मकसद राजमार्ग एवं माल ढुलाई गलियारों की सुधार परियोजनाओं के लिए

राज्य या स्थानीय सरकारों की तरफ से जारी प्राइवेट एक्टिविटी बॉन्ड्स (पीएबी) पर संघीय वैधानिक सीमा को 15 अरब डॉलर से 20.8 अरब डॉलर तक बढ़ाना है. सांसदों ने बताया कि इससे अमेरिकी परविहन विभाग (यूएसडीओटी) इन परियोजनाओं के लिए 5.8 अरब डॉलर की राशि की कर छूट वाले बॉन्ड जारी कर पाएगा.

युरो स्कुल में लव यु जिंदगी का आयोजन किया गया

सूरत। युरो स्कुल सूरत द्वारा लव यु जिंदगी थीम पर वार्षिक कोन्सर्ट का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा विषय के अनुरुप विविध प्रकार की आकर्षक कृतियों में किया गया। जिसमें हिला शक्तिकरण प्रमाण, मित्र, निष्ठा, प्रेम, ओनलाइन गेमिंग जैसे कई प्रकार की आकर्षक जलकिया पेश की जो आकर्षण का केन्द्र रही। 3 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों ने नृत्य और संगीतकला से उपस्थित मातापिता और स्कुल के स्टाफ का मन मोह लिया।

सूरत। 10-02-2019, रविवार के दिन समस्त वाटलिया प्रजापति ज्ञाति समाज में समुह लगन का आयोजन किया गया जिसमें समाज की 95 लड़कियों का विवाह होगा। जिसके तरत गुरुवार को सभी लड़कियों की महन्दी की रशम का आयोजन किया गया।

सरेआम युवक की धारदार हथियार से गोदकर हत्या

सूरत। शहर के मातावाडी सर्कल के निकट चार अज्ञात शक्सों ने सरेआम तीक्ष्ण हथियारों से गोदकर हत्या कर दी। पूरी घटना निकट लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है।

जानकारी के मुताबिक सूरत के वराछा क्षेत्र निवासी दिनेश वाडा नामक युवक हीरे तराशने का काम करता है। कल देर रात दिनेश अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में मातावाडी सर्कल के निकट चार अज्ञात शक्सों ने उसे घेर लिया और तीक्ष्ण हथियारों से उस पर हमला कर फरार हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल दिनेश वाडा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खबर मिलते ही वराछा पुलिस घटनास्थल पर

पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फूटेज मिले हैं, जिसमें चार श स दिनेश वाडा पर धारदार हथियार से हमला करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज के चार श सों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।

सबसे बड़ा कॉल सेन्टर प्रहलादनगर से पकड़ा गया

शहर से दो और बड़े अवैध कॉल सेन्टर पकड़े गये : ५४ गिरफ्तार

आपकी गाड़ी में से ड्रग्स-ब्लड सेम्पल मिले है बताकर डराते थे और लोगों से रुपये वसूलते थे : पुलिस जांच

अहमदाबाद । अहमदाबाद शहर से साइबर क्राइम के अधिकारियों ने प्रहलादनगर क्षेत्र से अभी तक का सबसे बड़ा अवैध कॉल सेन्टर पकड़े जाने से खलबली मच गई है। इसके साथ ही सोला पुलिस ने भी शीलज रोड पर से एक अन्य बड़ा अवैध कॉल सेन्टर का पर्दाफाश करने से सनसनी मच गई । शहर में विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करते दो इंटरनैशनल कॉल सेन्टर का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए ५४ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । आपकी गाड़ी पुलिस के कब्जे में है, जिसमें से ड्रग्स और ब्लड सेम्पल मिले है । यदि आपको खुद को बचाना हो तो पुलिस को गिफ्ट देना पड़ेगा यह बताकर विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करते कॉल सेन्टर का पर्दाफाश साइबर क्राइम ने करने से प्रहलादनगर के पेलेडियम कॉम्प्लेक्स से ३२ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अलग-अलग लोन की लालच देकर विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करते २२ युवकों की सोला पुलिस ने शीलज रोड पर स्थित अर्थ एसेन्स से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गत दिन विराटनगर में चल रहे कॉल सेन्टर पर साइबर क्राइम ने छापेमारी करके ८ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पिछले दो दिनों में तीन कॉल सेन्टर पर छापेमारी करके ६२ लोगों को गिरफ्तार किए जाने से सनसनी मच गई।

शहर के प्रहलादनगर के पेलेडियम कॉम्प्लेक्स में कई शख्स फर्जी कॉल सेन्टर चला रहे होने की जानकारी के आधार पर साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की गई थी और ३२ लोगों को गिरफ्तार किया गया । आपकी गाड़ी पुलिस के कब्जे में है, जिसमें से ड्रग्स और ब्लड सेम्पल मिले है, यदि आपको खुद को बचाना हो तो पुलिस को गिफ्ट देना पड़ेगा यह बताकर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करते थे । साइबर क्राइम ने आरोपियों से ३२ से ज्यादा कंप्यूटर, मेजिक जेक और स्क्रीट तथा डेटा कब्जे में लिया गया है । अमेरिका में कोई नागरिक की कार गुम हो गई हो इसकी जानकारी लेकर इसे कॉल करते थे और आपकी गाड़ी में से ड्रग्स और ब्लड सेम्पल मिले है। यदि आपको खुद को बचाना हो तो पुलिस को गिफ्ट देना पड़ेगा यह बताकर विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करते थे।

अहमदाबाद से साइबर क्राइम के अधिकारियों ने प्रहलादनगर क्षेत्र से अभी तक का सबसे बड़ा अवैध कॉल सेन्टर पकड़े जाने से खलबली मच गई है।

अहमदाबाद में जिसका इंतजार किया जा रहा था, यह अहमदाबाद मेट्रो का पहला ट्रायल रन गुरुवार को भारी उत्साह के माहौल के बीच सफ्लतापूर्वक पूरा किया गया ।

पुलिस बेटे सहित ८ आरोपियों की गिरफ्तारी

शाहीबाग पुलिस मुख्यालय से जुए का अड्डा पकड़ा गया

अहमदाबाद। शहर के शाहीबाग मुख्यालय में चल रहा जुए के अड्डे का पर्दाफाश देर रात को स्टेट मोनिटरींग सेल ने करते हुए पुलिसबेडा में सनसनी मच गई । क्योंकि शाहीबाग पुलिस मुख्यालय में जुआ खेल रहे जुआरियों दूसरे कोई नहीं पुलिस के बेटे ही थे । पुलिस ने पुलिस कर्मचारी और चार लाइनबॉय (पुलिस कर्मचारियों के बेटे) सहित ८ लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है । इस घटना से शाहीबाग पुलिस मुख्यालय और फिर एक बार विवादों में आ गया है। पुलिस वान से डीजल चोरी करते पुलिस कर्मचारी के बेटों की घटना सामने आने के अभी कुछ ही दिन हुए है अब मुख्यालय में देर रात को जुए का अड्डा पकड़े जाने से पुलिस की छवि के विरूद्ध गंभीर सवाल उठाये गये है।

शहर पुलिस का सभी काम पुलिस मुख्यालय से होता है । शाहीबाग में स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मचारियों को तालीम, वाहनों का आवंटन तथा डॉग स्क्वायड सहित अलग-अलग टीमें और पुलिस विभाग के एडमिन का सभी काम होता है।

वरिष्ठ अधिकारियों, सहित हजारों पुलिस कर्मचारी मुख्यालय में ड्यूटी करते हैं । पूरा दिन पुलिस के आवागमन से चल रहा मुख्यालय में अब क्राइम चल रहे होने की बात सामने आ रही है। पुलिस शहर में चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमारी करके कार्रवाई की जा रही है तब उनके ही मुख्यालय में जुए के अड्डा चल रहा है। स्टेट मोनिटरींग सेल को जानकारी मिली थी कि शाहीबाग पुलिस मुख्यालय के अंदर स्थित कम्युनिटी हॉल के पास खुले मैदान में जुए का अड्डा चल रहा है। मिली जानकारी के आधार पर स्टेट मोनिटरींग सेल के पुलिस कर्मचारियों ने इस मामले में पर्याप्त जांच की। जुए की जानकारी सही मिलने के साथ ही स्टेट मोनिटरिंग सेल ने देर रात को शाहीबाग मुख्यालय में स्थित खुले मैदान में छापेमारी की गई और जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया गया था।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)